

पौधरोपण प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रेरणादायी प्रयास : शर्मा

नवभारत, पनागर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन परिक्षेत्र पनागर अंतर्गत जैव विविधता प्रबंध समिति सुंदरपुर द्वारा ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत वृहद पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण में वृद्धि एवं जनसामान्य को प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा।

कार्यक्रम में वन परिक्षेत्र अधिकारी सौरभ शर्मा के नेतृत्व में विभिन्न पत्रालियों के पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान उपस्थित जनों को वृक्षों के महत्व एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने का संदेश दिया गया।कार्यक्रम में सुमित यादव (प्रांतीय अध्यक्ष, युवा सेवा संगठन), दीपक कश्यप (डिप्टी रेंजर), राम सजीवन दुबे, राजकुमार कुशवाहा, अंकित ठाकुर, पंकज कुमार सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणजनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। मुख्य अतिथि सौरभ शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान केवल पौधरोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति सम्मान और मातृ शक्ति के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक प्रेरणादायी प्रयास है। उन्होंने सभी नागरिकों से पौधारोपण के साथ-साथ पौधों के संरक्षण एवं देखभाल का भी



संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन एवं

पौधों के संरक्षण को लेकर उपस्थित लोगों को जागरूक किया गया। अंत में सभी प्रतिभागियों ने

लागाए गए पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण का संकल्प लिया।

पीएचसी बेलखाडू में मनाया विश्व पर्यावरण दिवस

नवभारत,बेलखाडू। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शासन के निर्देशानुसार मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ संजय जैन के निर्देशन एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. पीयूष द्विवेदी एवं डॉ.नीशमा सिद्दीकी के मार्गदर्शन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलखाडू में पर्यावरण संरक्षण एवं जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पीएचसी स्टाफ डाला परिसर में पौधारोपण किया गया तथा पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली गई। उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि वे प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएंगे, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं साफ-सुथरा बनाए रखेंगे, जल एवं बिजली की बचत करेंगे तथा जनसमुदाय को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का निरंतर प्रयास करेंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य केंद्र के समस्त कर्मचारियों ने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डाला और पक्षियों के लिए पानी के सकोरे लगाए,अधिक से अधिक पौधारोपण करने का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना तथा हरित एवं स्वच्छ वातावरण के निर्माण में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम में पीएचसी बेलखाडू के स्टाफ राकेश वर्मा, अजय चौबे, पूजा सेन, राधा ठाकुर शिखा शुक्ला, वीरेंद्र पटेल, मुकेश रजक, सिद्धांत ठाकुर की सहभागिता रही।



बीट प्रभारियों की साठगांठ से चल रहा अवैध खनन का खेल

नवभारत, मझौली। एक तरफ सरकार पर्यावरण बचाने के लिए करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा रही है, तो दूसरी तरफ मझौली के जंगलों को ‘साठगांठ का दीमक’ अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। यहाँ जंगलों को कुदरत या मौसम से नहीं, बल्कि वन विभाग के उन बीट प्रभारियों से खतरा है जो चंद रुपयों की खातिर अंधे और बहरे बन चुके हैं!

रातों रात जंगलों को साफ करके देखते ही देखते वहाँ अवैध कब्जे और खेती शुरू की जा रही है। बेखौफ माफिया जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर खुलेआम जंगलों में घुस रहे हैं। मोरम, पत्थर और मिट्टी का सीना चीरकर अवैध परिवहन किया जा रहा है। जब वन विभाग के पास बकायदा गश्ती दल है, तो बीट प्रभारियों को ये भारी-भरकम



जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉली क्यों नहीं आते? क्या ‘महीने की बंधी-बंधाई मोटी रकम’ ने इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। जंगलों की इस अंधाधुंध तबाही की सबसे बड़ी कीमत वन्यजीवों को चुकानी पड़ रही है। उनके प्राकृतिक घर उजड़ रहे हैं, जिससे वे गांवों और रिहायशी इलाकों की तरफ भागने को मजबूर हैं, जो किसी बड़े खतरे का संकेत है। वन विभाग के आला अधिकारी

इस पूरे खेल पर ‘रहस्यमयी खामोशी’ क्यों अखिरवार किए हुए हैं। क्या बीट प्रभारियों के इस ‘कमीशन’ का हिस्सा ऊपर तक जा रहा है।मुख्यमंत्री के ‘जीरो टॉलरेंस’ के दावों को मझौली का वन अमला खुलेआम ठेगा क्यों दिखा रहा है। जब तक इन भ्रष्ट बीट प्रभारियों को निलंबित कर जेल नहीं भेजा जाता, तब तक मझौली के जंगलों को बचाना नामुमकिन है!

गिरदावरी अधूरी, मूंग–उड़द पंजीयन टप

► समर्थन मूल्य खरीदी पर सरकार स्थिति स्पष्ट करें, पंजीयन तिथि बढ़ाने की मांग

नवभारत, पनागर। मूंग एवं उड़द की समर्थन मूल्य खरीदी के लिए शुरु किए गए पंजीयन कार्य में भारी अव्यवस्था सामने आ रही है। किसानों का आरोप है कि गिरदावरी कार्य पूरा न होने के कारण पंजीयन केंद्रों पर उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा, जिससे किसान परेशान और चिंतित हैं। इस मामले को लेकर भारतीय किसान संघ ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए

तत्काल स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।भारतीय किसान संघ महाकोशल प्रांत के प्रांत महामंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि मध्यप्रदेश सरकार ने मूंग एवं उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु 25 मई से 15 जून 2026 तक पंजीयन कराने के निर्देश जारी किए थे और इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया गया लेकिन जमीनी स्तर पर किसान जब पंजीयन केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, तब उन्हें यह कहकर वापस लौटना जा रहा है कि अभी तक गिरदावरी का कार्य पूरा नहीं

हुआ है। कई क्षेत्रों में गिरदावरी शुरू तक नहीं हो पाई है, जबकि पंजीयन की अंतिम तिथि नजदीक आ चुकी है। इससे किसानों में असमंजस और आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। भारतीय किसान संघ ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। संघ का कहना है कि सरकार तत्काल स्पष्ट करे कि मूंग–उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी या नहीं, ताकि किसानों को अनिश्चितता की स्थिति में न रहना पड़े। साथ ही गिरदावरी कार्य युद्धस्तर पर पूरा कराया जाए तथा गिरदावरी पूर्ण

अवैध प्लांटिंग का जाल, प्रशासन मौन

नवभारत सिहोरा । शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों अवैध प्लांटिंग का कारोबार तेजी से फैलता जा रहा है। बिना किसी वैधानिक अनुमति और नियमों का पालन किए भू-माफिया खुलेआम कृषि भूमि को छोटे-छोटे प्लॉट में काटकर बेच रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल पर जिम्मेदार विभागों की नजर होते हुए भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

जानकारी के अनुसार, सिहोरा के बाहरी इलाकों में कई जगहों पर खेती योग्य जमीन को बिना डायवर्जन करए ही प्लांटिंग कर

बेचा जा रहा है। न तो इन कॉलोनियों में सड़क, नाली, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था है, फिर भी लोगों को सस्ते दाम का लालच देकर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। इससे खरीदारों को भविष्य में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे भू-माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं, नगर एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है।



पर बनी इस बीआरसी यूनिट का निरीक्षण करने आज स्वयं डॉ. त्रिपाठी पहुंची कृषक अभेंद्र सिंह जी के फार्म पर पहुंची। उन्होंने बीआरसी यूनिट का बारीकी से निरीक्षण किया और इसे आधुनिक कृषि का एक आदर्श केंद्र बताया। डॉ. त्रिपाठी ने कहा कि यह यूनिट इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे कम लागत में वैज्ञानिक और प्राकृतिक तरीकों का समन्वय करके खेती को अत्यधिक लाभप्रद बनाया जा सकता है।

व्यों है यह एक आइडियल यूनिट कृषक अभेंद्र सिंह चंदेल पिछले कई वर्षों से पूर्णतः प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और उनकी इस निष्ठा के कारण उन्हें (मध्य प्रदेश स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी) द्वारा आधिकारिक जैविक प्रमाणीकरण भी मिल चुका है। उनकी इस यूनिट को ‘आदर्श’ बनाने के पीछे कई खास वजहें हैं। कम्प्लीट इन-हाउस प्रोडक्शन: इस सिंगल यूनिट के भीतर ही उच्च

गुणवत्ता युक्त वर्मिकोपोस्ट (केंचुआ खाद), घन जीवामृत, तरल जीवामृत और फसलों को कीटों से बचाने के लिए कई प्रकार के जैव रसायन वैज्ञानिक पद्धति से तैयार किए जाते हैं। किसान को खाद या कीटनाशक के लिए बाजार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जैविक गन्ना और वैल्यू एडिशन (मूल्य संवर्धन): अभेंद्र सिंह न सिर्फ जैविक गन्ना उगाते हैं, बल्कि अपनी यूनिट के सहयोग से उसी गन्ने से शुद्ध ‘जैविक गुड़’ भी तैयार करते हैं। कच्चे माल को सीधे बेचने के बजाय उसका प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनाना इस यूनिट को औरों से अलग और आदर्श बनाता है।

‘जैविक हाट’ न दिया पंख, अधिकारी ने दी ‘स्मार्ट पैकेजिंग’ की सलाह जिला कृषि विभाग द्वारा

संचालित साप्ताहिक जैविक हाट इस आदर्श यूनिट के लिए एक वरदान साबित हुआ है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए अभेंद्र सिंह को अपने उत्पादों का सीधा और उचित मूल्य मिल रहा है, जिससे वे बेहद प्रोत्साहित हैं। निरीक्षण के दौरान डॉ. इंदिरा त्रिपाठी ने इस आइडियल यूनिट की गन्ना और वैल्यू एडिशन (मूल्य संवर्धन): अभेंद्र सिंह न सिर्फ जैविक गन्ना उगाते हैं, बल्कि अपनी यूनिट के सहयोग से उसी गन्ने से शुद्ध ‘जैविक गुड़’ भी तैयार करते हैं। कच्चे माल को सीधे बेचने के बजाय उसका प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनाना इस यूनिट को औरों से अलग और आदर्श बनाता है।

जिला कृषि विभाग द्वारा

जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर रेल यात्री



कि स्टेशन पर बना मौजूदा फुट ओवर ब्रिज केवल मुख्य लाइन को पार करने के लिए ही पर्याप्त है।रेलवे साइडिंग यार्ड में खड़ी रहने वाली मालगाड़ियों के उस पार जाने के लिए कोई फुट ओवर ब्रिज नहीं है। इस वजह से यात्रियों को अपनी जान जोखिम में डालकर, खड़ी मालगाड़ियों के नीचे से रेंगकर (आर-पार) निकलना पड़ता है।

किसी भी समय मालगाड़ी के अचानक चलने से यहाँ कोई भी बड़ा और दर्दनाक हादसा हो सकता है। इस अव्यवस्था का सबसे बुरा अरर क्षेत्र के दैनिक यात्रियों पर पड़ रहा है। रोजाना कॉलेज और स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राएं, दफ्तर जाने वाले कामकाजी लोग और बुजुर्ग महिलाएं इस खतरनाक स्थिति से गुजरने को मजबूर हैं।स्थानीय लोगों का कहना है कि एक तरफ सरकार रेल यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ गोसलपुर में यात्रियों को बुनियादी सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही है।

बाइक सवार को घसीटता ले गया वाहन,मौत

► नेशनल हाईवे 34 एन एच-34 पर रमनपुर के समीप पहुंचा तभी सामने से आ रहे एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर लगते ही गंगाराम उछलकर दूर जा गिरो। इसके बाद भी अज्ञात वाहन नहीं रुका और वह गंगाराम को रौंदते हुए काफी दूरी तक घसीटता चला गया। शरीर में आई गंभीर चोटों और अत्यधिक खून बह जाने के कारण गंगाराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद अज्ञात चालक मौके से फरार हो गया। इसके बाद राहगीरों द्वारा दुर्घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों और हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से फरार वाहन और उसके चालक की सरगमी से तलाश की जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बाइक चालक गंगाराम जैसे ही एनएच-34 पर रमनपुर के समीप पहुंचा तभी सामने से आ रहे एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर लगते ही गंगाराम उछलकर दूर जा गिरो। इसके बाद भी अज्ञात वाहन नहीं रुका और वह गंगाराम को रौंदते हुए काफी दूरी तक घसीटता चला गया। शरीर में आई गंभीर चोटों और अत्यधिक खून बह जाने के कारण गंगाराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद अज्ञात चालक मौके से फरार हो गया। इसके बाद राहगीरों द्वारा दुर्घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों और हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से फरार वाहन और उसके चालक की सरगमी से तलाश की जा रही है।

कार्रवाई दर्शनी पंचायत के सरपंच सुमित राय बर्खास्त, 50 हजार के भुगतान ने खोली सत्ता के दुरुपयोग की पोल

पिता को पहुंचाया सरकारी लाभ, हाथ से गई सरपंची

नवभारत, मझौली। जनपद पंचायत मझौली की ग्राम पंचायत दर्शनी में सत्ता के दुरुपयोग और पारिवारिक लाभ पहुंचाने का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पंचायत व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला पंचायत जबलपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी ने ग्राम पंचायत दर्शनी के सरपंच सुमित राय को उनके पद से तत्काल प्रभाव से पृथक (बर्खास्त) कर दिया है। आरोप है कि सरपंच ने अपने पद और प्रभाव का उपयोग करते हुए पंचायत निधि से अपने ही पिता संतोष राय के खाते में 50,000 का भुगतान कराया। मामले की जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद जिला पंचायत प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया।



एक शिकायत और खुल गया पूरा खेल

मामले की शुरुआत ग्राम पंचायत दर्शनी निवासी मोहन झारिया की शिकायत से हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पंचायत निधि का उपयोग नियमों को ताक पर रखकर सरपंच के परिजनों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। जिला पंचायत स्तर पर शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए गए। जनपद

पंचायत मझौली द्वारा गठित जांच दल ने पंचायत दर्पण पोर्टल, भुगतान अभिलेख, विल वाउचर और अन्य दस्तावेजों का परीक्षण किया। जांच में शिकायत को सही पाया गया।

तीन किस्तों में पिता के खाते में पहुंची राशि

जांच प्रतिवेदन के अनुसार पंचायत निधि से कुल50,000 की राशि सरपंच के पिता संतोष राय के खाते में स्थानांतरित की गई थी। भुगतान का विवरण-15,000

— विधायक निधि अंतर्गत रंगमंच निर्माण कार्य।15,000 — खनिज मद से सामुदायिक भवन निर्माण कार्य। 20,000 — विधायक निधि अंतर्गत रंगमंच निर्माण कार्य तीनों भुगतान नवंबर 2023 में किए गए और सरकारी अभिलेखों में सफल भुगतान दर्ज पाया गया।

बचाव में गद्दी गई ‘नकद भुगतान’ की कहानी

जांच के दौरान सरपंच सुमित राय, पंचायत सचिव भीष्म सिंह और एक ईंट विक्रेता ने दावा किया कि पंचायत निर्माण कार्यों के लिए खरीदी गई ईंटों का भुगतान पहले संतोष राय ने अपनी निजी राशि से किया था। उनका कहना था कि ग्राम गुरजी के ईंट व्यवसायी रामभैया इक्रवर्ती को 10 हजार ईंटों के एवज में 50,000 नकद दिए गए थे, इसलिए बाद में वही राशि पंचायत निधि से संतोष राय को वापस की गई। ईंट विक्रेता ने

भी इसी कथन का समर्थन किया, लेकिन जांच और न्यायिक परीक्षण में यह तर्क कानून की कसौटी पर टिक नहीं पाया।

न्यायालय की दो टूक : ‘रिश्तेदार को लाभ पहुंचाना कानूनन अपराध मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों, गवाहों के बयानों और प्रतिपरीक्षण का परीक्षण करने के बाद विहित प्राधिकारी ने स्पष्ट कहा कि पंचायत पदाधिकारी अपने पद का उपयोग किसी भी नातेदार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने के लिए नहीं कर सकता।

लोकाहित में पद पर बने रहना माना गया अनुचित अपने आदेश में विहित प्राधिकारी ने टिप्पणी की कि ऐसा पदाधिकारी जो अपने अधिकारों का उपयोग निजी बने पारिवारिक हित साधने के लिए करता है, उसका पंचायत पद पर बने रहना लोकाहित में उचित नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर धारा 40(क) एवं 40(ख) के तहत सुमित राय को तत्काल प्रभाव से सरपंच पद से पृथक कर दिया गया।